कॉर्ड–11014/7/2019-समन्वय
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
(समन्वय प्रभाग)
****

तृतीय तल, कौशल भवन,
न्यू मोती बाग, नई दिल्ली–110023
दिनांक: 30 मई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एसडीई मंत्रालय से संबंधित मंत्रीमंडल के लिए मासिक सार– के संबंध में

मुझे अप्रैल, 2024 के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार सूचनार्थ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त

30/05/2024

(अखिलेश कुमार राय)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रति:

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110001

अप्रैल, 2024 माह के दौरान इस मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियाँ/प्रयास

1. **लघु व्यवसाय विकास इकाइयों (एसबीडीयू) का शुभारंभ:** एमएसडीई ने, आईआईएम जम्मू के सहयोग से, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 22 मौजूदा कौशल केंद्रों को लघु व्यवसाय विकास इकाइयों (एसबीडीयू) में बदलने के लिए "लघु व्यवसाय विकास इकाइयां (एसबीडीयू)" प्रारंभ की है। इन इकाइयों का लक्ष्य स्थानीय छोटे व्यवसायों और आसपास के इच्छुक उद्यमियों को सहायता और मार्गदर्शन तंत्र प्रदान करना है। एसबीडीयू में परिवर्तन का उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को "जॉब चाहने वालों" के बजाय "जॉब निर्माता" के रूप में विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है। वे छोटे उद्यमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और गतिमान करने के लिए व्यापक व्यवसाय इनक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करके इसे हासिल करेंगे। इस पहल के तहत, कुल 127 उद्यमियों ने लघु व्यवसाय विकास प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लिया है। इसमें अप्रैल 2024 के दौरान 25 उद्यमियों का प्रशिक्षण शामिल है।

2. **"व्यापक उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" परियोजना का कार्यान्वयन:** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के साथ भागीदारी में, “पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए व्यापक उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह पहल उद्यमिता और कौशल विकास में एक व्यापक 30-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करके पीएम वन-धन-योजना (पीएमवीडीवाई) और ‘स्फूर्ति’ स्कीमों के तहत लाभार्थियों के उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्पाद विकास, वित्तीय प्रबंधन और विपणन रणनीतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। अप्रैल 2024 तक, 167 बैचों में कुल 4,175 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, और उनका प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है।

3. ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म उद्यमियों को सक्षम करना (डीएलआई-7): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संकल्प पहल के तहत (डीएलआई-7 परियोजना के लिए "ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म उद्यमियों को सक्षम करने" के लिए हाथ मिलाया है। यह परियोजना वर्तमान में छह राज्यों: आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करके सेवा प्रदेयता को बढ़ाना है। अप्रैल 2024 तक, 4,335 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, 1,145 का मूल्यांकन किया गया है, 858 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है, और 729 उम्मीदवार वर्तमान में 90 ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। संचयी रूप से, इस परियोजना ने 499 ग्राम पंचायतों के 6,670 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

4. **अम्बर परियोजना का कार्यान्वयन:** एमएसडीई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की सहभागिता से, वर्तमान में संकल्प पहल के तहत अम्बर परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जॉब नियोजन और जॉब प्रतिधारण की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। परियोजना का लक्ष्य 30,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, विशेष रूप से समकालीन प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते

हुए उच्च-परिमाण प्रौद्योगिकी-उन्मुख जॉब रोल्स पर ध्यान केंद्रित करना है। अप्रैल 2024 तक, कुल 26,346 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 19,545 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया और 17,638 को प्रमाणित किया गया। केवल अप्रैल 2024 के दौरान, 3,081 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया, और 2,609 को प्रमाणित किया गया।

5. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) द्वारा किए गए कार्यकलाप: जेएसएस, अभिसरण के हिस्से के रूप में, सरकार की प्रमुख योजना, अर्थात् पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी) को कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना के विभिन्न ट्रेडों के तहत पूरे भारत में 69 जेएसएस में पीएमवी के तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया है। 18 जेएसएस के प्रबंधन बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है। पंजीकरण प्रक्रियाओं, विकसित की जाने वाली वित्तीय कार्यक्षमताओं और मौजूदा जेएसएस पोर्टल से एसआईडीएच में स्थानांतरित किए जाने वाले अन्य मॉड्यूल पर चर्चा के संबंध में एनएसडीसी के अधिकारियों के साथ 19 अप्रैल 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

6. कौशल एकीकृत उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईएसएचई): क्रिस्प द्वारा शुरू की गई 'कौशल एकीकृत उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईएसएचई)' पर 24 अप्रैल 2024 को कौशल भवन, नई दिल्ली में एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की गई थी। एनआईएसएचई का उद्देश्य सामान्य शिक्षा को बाजार-मांग आधारित पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत करना, उद्योग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्थागत बनाना और डिग्री पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के हिस्से के रूप में शिक्षुता को एकीकृत करना है। पाठ्यक्रम को उद्योग और विश्वविद्यालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से डिजाइन किया जाना है। कर्नाटक राज्य के 20-डिग्री कॉलेजों में प्रायोगिक पहल शुरू की गई है। इस परामर्शदात्री बैठक में एमएसडीई, कर्नाटक राज्य सरकार, कर्नाटक राज्य के डिग्री कॉलेज, क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) और सीआरआईएसपी के अधिकारियों ने भाग लिया।

7. आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी): राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस-2) के तहत, 09 अप्रैल, 2024 को कौशल में संयुक्त सचिव (एटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस-2) के तहत आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के कार्यान्वयन के संबंध में पोर्टल पर प्रगति का पता लगाने और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई, पीएफएमएस और एनएसडीसी के साथ कौशल भवन में एक बैठक आयोजित की गई थी।

8. बैठकें, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ:

(क) शिक्षुता प्रशिक्षण स्थिति: दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संबद्ध किए गए शिक्षुओं की संख्या 36,751 है। दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षुओं की कुल संख्या 7.4 लाख है। दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शिक्षुओं को नियुक्त/नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 45,692 है।

(ख) डीबीटी स्थिति: डीबीटी को राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के तहत 11-08-2023 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता (एसडीई) मंत्री द्वारा किया गया। डीबीटी के माध्यम से भाग लेने वाले शिक्षुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और जुलाई 2023 (1,64,652) से अप्रैल 2024 (2,85,134) तक 73% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, 315.59 करोड़ रुपये की वृत्तिका की भारत सरकार की हिस्सेदारी डीबीटी के माध्यम से शिक्षुओं को वितरित की गई है।

(ग) **सीएससी (ग्राम स्तर के उद्यमियों की ऑनबोर्डिंग):** सीएससी में शिक्षुता संबद्धता का समर्थन करने के लिए, सीएससी से लगभग 33,250 वीएलई का विवरण शिक्षुता पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ये वीएलई भारत भर के 29 राज्यों से हैं। अप्रैल माह में, 5 और 12 अप्रैल 2024 को संयुक्त सचिव (एटी) की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गईं। स्कीम दिशानिर्देश, स्कीम के लाभ और पोर्टल डेमो आदि पर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की सीएससी टीम के साथ कुल 5 नियमित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए हैं।

(घ.) **ग्लोबल स्किल्स फोरम**: ग्लोबल स्किल्स फोरम 23 और 24 अप्रैल 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आईएलओ मुख्यालय में आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव, एमएसडीई ने 'गुणवत्ता शिक्षुता अनुशंसा 208' पर सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

9. **परिचालन दक्षता:** उपर्युक्त पहलों के अलावा, सभी निपटान योग्य कार्यों के शीघ्र निपटान में अत्यधिक तत्परता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई आंतरिक उपायों के माध्यम से कार्य निष्पादन को युक्तिसंगत बनाने की चल रही प्रक्रिया जारी रही।